Postal Registration No. G/CHD/0107/2012-14 RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

# जाट लहर

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

वर्ष 14 अंक 09 30 सितम्बर, 2014 मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से

## ताऊ का सफर

### ( २५ सितंबर १०१ वें जन्म दिवस पर विशेष )

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

ताऊ का सफर आसान ना था, जो मुकाम ताऊ देवीलाल ने अपने जीवन में ही हासिल कर लिया वह विश्व इतिहास में एक अनुठी मिशाल है। उन्होने यह सफर घर से ही अपनी खुद की सैंकड़ों एकड़ जमीन मुजारों को देकर, सर्वोदय में शामिल हो भू-दान आहूति देकर शुरू किया। वे सर्वदा एक यौद्धा की तरह संघर्षरत रहे और किसान, कामगार व काश्तकार के पैरोकार रहे। वे सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर सदैव जन साधारण के हितों के लिए प्रयास करते रहे। मुख्यमंत्री के तौर पर १९८७-८९ में उनकी टांगों में सूजन आ गई लेकिन डाक्टरों की सलाह के बावजूद उन्होने आराम नहीं किया। उल्टे बर्फ की पट्टियां बांधकर सफर किया और सदा खेत खलिहान में हर एक का दुख सुख सुनने पहुंचते रहे। एक बार बाढ़ आई तो चौधरी साहब खुद कसी तसला लेकर हर गांव के गिर्द रिंग बांध बनाने पहुंच गए। फसल के आसार अच्छे न हो, देरी हो रही हो वे अपनी भूमिका कभी नहीं भूले। फ सल बुआई में देरी के मद्देनजर उन्होने सरकारी तौर पर ट्रैक्टरों की व्यवस्था करवाई और सरसों की बुआई करवाई।

आज किसान की फसलों के लागत मुल्यों में निरंतर हो रही वृद्धि पर किसी को चिंता नहीं है। गत १ वर्षों में किसान की लागत में इजाफा ही हुआ है, कहीं भरपाई का नामो निशान नहीं। या इस अवस्था में चौधरी देवी लाल कभी चुप बैठ सकते थे। उन्होने विवधिकरण से नकद राशी वाली फसलों को सुझाया, प्रयोगशाला से किसान के खेत तक योजना चालू करवाई ताकि किसान के घर सुख समृद्धि आए, उसके बच्चे पढें लिखें तथा सम्मान से जीवन यापन कर सकें। इसीलिए आज हरियाणा का बच्चा-बच्चा पुकार पुकार कर कह रहा है ''उठ दर्द मदां दे दर्ददिया ते तक अपना अस्थान'' किसान के खेत को पानी नहीं, उसके बेटे को उचित शिक्षा नहीं, अगर वो पढ गया तो रोजगार नहीं। आज फिर मांग हो रही है, ताऊ आए और - ''भ्रष्टाचार बंद, पानी का प्रबंध'' करे, किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए पक्के खालों की व्यवस्था का जीर्णोद्धार हो। प्रशासन पुनः जनता के दरबार में आए 'कन्या दान' वृद्धावस्था सम्मान पैशन जैसी कल्याणकारी योजनाएं सुचारू हो। आज कागजों में सब कुछ है 1 क्योंकि ताऊ द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को हटाना संभव नहीं अन्यथा यह भी हो जाता। लोक राज लोक लाज से ही चले, कोरे आश्वासनों से जनता को कब तक गुमराह किया जा सकता है इसका निर्णय जनता आगामी चुनाव १५ अक्तुबर २०१४ को कर देगी।

चौधरी देवी लाल किसान, गरीब, मजदूर किसी की भी आपदा के लिए वे द्रवित हो उठते थे। उनके द्वारा किसानों के ऋण माफ करना तथा उनकी भूमि के रिकार्ड के उचित रख रखाव हेतू किसान पास बुक शुरू करवाना गरीब, किसान-काश्तकार के हित में महत्वपूर्ण प्रयास थे। सर छोटू राम जैसे महान नेताओं ने किसान के हित की बात सोची लेकिन किसान की हर दिक्कत, मौसम की खराबी, हर हाथ को रोटी, हर खेत को पानी, शिक्षा का प्रचार प्रसार, शहरीकरण की होड़ में देहात से शहर की ओर हो रहे पलायन की रोकथाम हेतू चौधरी देवीलाल ही सोच सकते थे। उनकी कथनी और करनी में अंतर ना था, वे गांधी जी के उपासक थे क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वास्तविक भारत गांव में बसता है। भारत की ८ प्रतिशत आबादी देहात में बसती है लेकिन सुविधाओं की कमी इसी क्षेत्र में है। चौधरी देवीलाल ने देहात में ही सहुलियतें उपलब्ध करवाने की सोची। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में पानी की उपलब्धता, हर गांव तक पक्की सड़क, गरीब मजदूर के घर में एक बल्ब रोशनी के लिए प्रावधान, मानव तथा पशु चिकित्सा की व्यवस्था, गांव गांव में स्कूल तथा घुमंतू परिवारों के बच्चों को स्कूल में रखने के हाजरी के लिए प्रतिदिन एक रूपया देना। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू कर देहात से पलायन को रोकने का प्रयास किया। बुढापा सम्मान पैंशन योजना शुरू कर बुजुर्गो को सम्मान दिया। महिला प्रसूति पर जच्चा-बच्चा योजना व सुखमय विवाहित जीवन हेतू कन्यादान योजना शुरू की।

ताऊ देवीलाल का अटूट विश्वास वर्गहीन, जातिवाद धर्मविहिन, भेदभाव रहित और गुटविहिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में था। उनकी राजनीति केवल जनहित पर आधारित थी। उनका प्रयास था समाज का शोषित वर्ग, शोषण मुक्त हो। ताऊ देवीलाल ने राजनीतिज्ञों के लिए लोकलाज के आदर्श के

-शेष पेज 2 पर

'k"k i!t &1

अंतर्गत आचार संहिता लाने पर बल दिया ताकि राजनीति में अनैतिकता को आने से रोका जा सके। उन्होने राजनीति को जीवन मूल्यों तथा जीवनादर्शों से जोड़ने का यत्न किया और वे चाहते थे कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जनहित कार्य न करने पर आम जनता को उन्हे वापिस बुलाने का अधिकार होना चाहिए।

समाज के हर वर्ग से मिट्टी के कण-कण की तरह जुड़े हुए व पूर्णतया ग्रामीण पृष्ठभूमि के धनी चौ0 देवीलाल का जन्म 25 सितंबर सन 1914 को हरियाणा के सिरसा जिले के गांव तेजा खेड़ा के किसान परिवार में हुआ। युगपुरूष चौ0 देवीलाल भारतवर्ष के एक ऐसे नेता रहे हैं, जिनका संपूर्ण जीवन संघर्षो से भरा हुआ है। आजादी से पहले वे आजादी के बाद के इतिहास को देखा जाए तो संघर्ष के उल्लेख में चौ0 देवीलाल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा नजर आता है। ये संघर्ष सदैव किसानों, गरीबों, मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए लड़ा गया। महज 16 वर्ष की आयु में ही सन 1933 में महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। अभी चौ0 देवीलाल के विवाह को मात्र महीने ही हुए थे, आजादी के आंदोलन में पहली बार जेल भेज दिए तथा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान सात बार जेल काटनी पड़ी।

जिस गिरते लिंग अनुपात के लिए भारत सरकार आज चिंतित हो रही है, चौधरी साहब ने 'कन्या दान' आज से वर्ष पूर्व देकर समाधान दे दिया था। स्त्री शिक्षा पर उन्होने विशेष बल दिया था। मुफ्त वर्दी, पाठन सामग्री के साथ-साथ आठवीं तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान चौधरी देवी लाल ने दिया था ताकि शिक्षित नारी, घर परिवार को सुचारू रूप से चला सके, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे सके। उनका कथन था कि नारी शिक्षा से दो परिवार शिक्षित होते हैं। मुफ्त साईकिल उन्ही के सपूत चौधरी औमप्रकाश चौटाला की देन है तथा घुमंतू कबीलों के परिवारों के बच्चों को स्कूल हाजरी का प्रतिदिन एक रूपया चौधरी साहब ने दिया जो चौटाला जी ने मंहगाई के मद्देनजर पांच रूपये कर दिया।

छोटे काश्तकारों को उनका अधिकार दिलाने हेतू पंजाब विधानसभा में भू-पट्टेदारी अधिनियम 1953 बनवाकर मुजारों की बेदखली को रोका गया। इस अधिनियम के द्वारा 6 साल से भूमि काश्त कर रहे मुजारों को अदालत के माध्यम से आसान किश्तों पर जमीन खरीदने का अधिकार दिलाकर मालिकाना हक भी दिलवाया। सरकारी कोष से जारी धनराशी के सदुपयोग व ग्रामीण समाज के समुचित विकास के लिए ग्रामीण जनता द्वारा एकत्रित धनराशी पर सरकारी खजाने से दो या तीन गुणा अनुदान दिलाकर लगातार मैचिंग ग्रांट योजना शुरू करने व राज्य कोष से जारी धनराशी को सीधे पंचायत व लोक स्तर पर खर्च करने के पारदर्शी व स्पष्ट प्रावधान लागू किए।

अपने संघर्षशील जीवन में चौ0 देवीलाल हार-जीत का परवाह किए बिना निष्काम सेवा भाव से जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे। वे सन् 1952, सन् 1959, सन् 1962 में तीन बार पंजाब विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए तथा सन् 1956 में तत्कालीन संयुक्त पंजाब में मुज्य संसदीय सचिव भी रहे। वे अपनी दूरदर्शी व पारदर्शी सोच के द्वारा हर प्रकार की समस्या का समाधान निकाल लेते थे। राष्ट्रहित में किसी भी राजनैतिक व सामाजिक मुद्दे पर वे अपने विरोधियों तक से भी सलाह मश्विवरा करने में संकोच नहीं करते थे। अपनी निष्कपट, निस्वार्थ व त्यागी छवि के कारण वे समस्त राष्ट्र में 'ताऊ' के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसीलिए उन्होने सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर 14-8-1985 को अपने तमाम विधायकों के साथ विधानसभा से इस्तिफा दे दिया। तत्पश्चात कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जींद में एक ऐतिहासिक रैली करके प्रथम न्याय युद्ध की शुरूआत की और वर्ष 1987 में विधानसभा की 90 सीटों में से 85 सीटें जीतकर नया रिकार्ड स्थापित किया।

पुलिस प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त करने हेतू पुलिस कर्मियों के लिए उन्हे समयबद्ध तरक्की देना, पूरे राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ पुलिस विभाग के खिलाड़ियों को भी खेल जगत में अव्वल प्रदर्शन करने पर विशेष तरक्की देना व ए एस आई के पद तक खिलाड़ी कोटे से 3 प्रतिशत विशेष भर्ती करने का प्रावधान आदि अनेकों कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। कुश्ती जैसे परंपरागत खेल को पूरे राष्ट्र में सर्वप्रथम वर्ष 1988 में राज्य खेल घोषित किया। वास्तव में प्रदेश में खेलों के विकास की परंपरा जन नायक चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी।

उनका विचार था कि देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पर दलित व प्रधानमंत्री के पद पर किसान/कामगार को आसीन करके ही महात्मा गांधी का समृद्ध व स्वावलंबी भारत का सपना पूरा हो सकता है। वास्तव में जन नायक महान तपस्वी व त्याग की मूर्ति थे। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि एक प्रभावशाली, कुशल राजनीतिज्ञ तथा सफल नेतृत्व के धनी होते हुए भी उन्होने दो बार अपने सिर से प्रधानमंत्री का ताज उतार दिया और स्वंय इसी ताज को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह व चंद्रशेखर के सिर पर रख दिया। उनके इस महान त्याग की भावना से आज उनके विरोधी भी मात खा रहे हैं। वे सदैव कहते थे कि ''मैं सत्ता के गलियारों की बजाए अपने प्रिय सीधे साधे लोगों के साथ रहना अधिक पसंद करता हूं''। उनका यह कथन दीन बंधू सर छोटूराम के विचारों के अनुकूल है ज्योंकि दीन बंधु भी सदैव यह कहा करते थे ''नहीं चाहिए मुझे मखमल के मरमरे, मेरे लिए तो मिट्टी का हरम बनवा दो।''

चौ0 देवीलाल ने अपने शासनकाल में सबसे पहले गरीब-

मजदूरों, छोटे दुकानदारों व काश्तकारों के व्यावसायिक व कृषि ऋण माफ करके समाज के सभी वर्गों को राहत पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू किया। इसके अतिरिक्त उन्होने काश्तकारों व छोटे दुकानदारों को बैंकों से सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने व कृषि के लिए बिजली, पानी, उत्तम बीजों, उर्वरकों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाने तथा प्राकृतिक प्रकोपों से फसल नष्ट होने पर किसानों व काश्तकारों को उचित मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था करके कृषि व इससे संबंधित कार्यों पर आधारित लगभग 8 प्रतिशत ग्रामीण जन संख्या के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया। किसान के खेत के चारों तरफ सामाजिक वानिकी के वे कर्णधार थे ताकि किसान की फसल का नुकसान भी ना हो और वृक्षों से अतिरिक्त आय भी हो सके। किसान के खेत के साथ लगे सरकारी वृक्षों से छाया की वजह से किसान को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए उन्होने वृक्ष की आमदन में आधा हिस्सा किसान को दिलवाया था।

आज आवश्यकता है कि ताऊ देवीलाल की नीतियों व सिद्धांतों का अनुशरण किया जाए। इससे सरकारी नीति व कार्यशैली निर्धारण में मदद मिलेगी। चौधरी साहब की जन कल्याणकारी योजनाओं व निश्छल राजनीति से प्रेरणा लेकर प्रशासनिक व राजनैतिक तंत्र की विचारधारा को बदलने की नितांत आवश्यकता है ताकि ग्रामीण गरीब-मजदूर व किसान वर्ग के कल्याण व उत्थान के साथ-साथ स्वच्छ प्रशासन के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। वास्तव में ताऊ देवीलाल गरीब व असहाय समाज की आवाज को बुलंद करने वाले एक सशक्त प्रवक्ता थे इसलिए आज जन साधारण विशेषकर ग्रामीण गरीब-मजदूर, कामगार व छोटे काश्तकारों को अपने अधिकारों व हितों के प्रति जागरूक करने की आवश्कता है ताकि दलगत राजनीतिज्ञ व संबंधित प्रशासन इनके हितों की अनदेखी न कर सकें तभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक स्वावलंबी व स्वस्थ ग्रामीण समाज का सपना पूरा किया जा सकता है। अतः एक उदार हृदय एवं महान आत्मा - ताऊ देवीलाल को लेखक सदैव नत मस्तक होकर प्रणाम करता रहेगा।

लेखक 1977 से 1979, 1987 से 1989 तथा अगस्त-सिंतबर 1999 से 6 सिंतबर 2001 तक चौधरी साहब के प्रशासनिक अधिकारी तथा पुलिस प्रमुख (गुप्तचार विभाग) रहे हैं।

**डा0महेन्द्र सिंह मलिक**
**आई0पी0एस0(सेवा निवृत)**
**पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं**
**राज्य चौकसी ब्यूरौ प्रमुख, हरियाणा**
**प्रधान, जाट सभा चंडीगढ़ एवं**
**अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति**

---

# *विकसित राष्ट्र के सपने सच करेगा विजन – 2020*

Mk- ,-ih-t- vCny dyke] iow jk"Vifr

विजन 2020 के तहत भारत को वर्ष 2020 तक विकसित मुल्क बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। रोडमैप तैयार है, उसके तहत गांवों में शहरों जैसी सुविधायें पंहुचाने का लक्ष्य था। यकीनन अभी तक काफी कुछ हासिल किया जा चुका है लेकिन सफर लंबा है। अधिक जानकारी के लिये पढ़ें पूर्व राष्ट्रति का यह ज्ञान वर्धक लेख।

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के हमें एक ऐसे राष्ट्र का ^^fotu** लेकर आगे बढ़ते रहना है, जिसके बाशिदें गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हों। उनकी शिक्षा और सेहत स्तरीय हो तथा राष्ट्र की सुरक्षा बिलकुल अचूक हो। इसके साथ ही तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मुल्क की उत्पादन क्षमता ऐसी गुणवत्तापूर्ण हो कि उससे देश में चौतरफाा खुशहाली आए और हमेशा कायम रहे।

इस तरह के विजन की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया दो दशक से पहले शुरू हुई थी। कई सारे लोगों ने दिन–रात परिश्रम करके इसे तैयार किया था। आज 1990 के दशक के अपने उन अनुभवों को मैं आपसे साझा करता हूं, जो साल 2020 के भारत के fotu से जुड़े है। मैंने टेक्नोलॉजी इनफॉर्मेशन, फॉरकास्टिंग ऐंड एसेसमेंट कौंसिल (टीआईएफएसी) की सदारत को इसकी जिम्मेदारी दी थी। यह एक स्वायत्त संस्था है, जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत 1988 में गठित हुई। राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट क्षेत्रों में इनोवेशन की सहायता और टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए इसका गठन हुआ था। इसकी पहली ही बैठक में कौंसिल के सदस्यों ने फैसला किया था कि साल 2020 तक भारत को आर्थिक रूप में विकसित राष्ट्र में बदलने की योजना यह परिषद तैयार करेगा।

यह वह समय था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव द्वारा शुरू आर्थिक उदारीकरण का असर दिखने लगा था और कौंसिल के सदस्य इसे लेकर आशंकित थे कि इस बदलते आर्थिक–सामाजिक हालात में हम कैसे एक दीर्घकालिक योजना तैयार कर सकते हैं, जबकि बीस साल बाद के हालात बिल्कुल अलग होंगें। उस समय देश की अर्थव्यवस्था करीब पांच–छह फीसदी की सालाना दर से बढ़ रही थी और हमें अगले दस वर्षों के लिए कम से कम दस फीसदी की विकास दर के बारे में सोचना था, ताकि देश की लोकतांत्रिक, बहुभाषी, बहुधार्मिक व बहुसांस्कृतिक आबादी का विकास हो सके।

^Vhvkb],Q,lh* की टीम ने दूसरे विभागों के

साथ मिलकर दो वर्षों से भी अधिक समय तक इस पर काम किया ओर करीबपच्चीस रिपोर्टें तैयार की गई। इनमें विविध क्षेत्रों, जैसे कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, नागरिक उड्डयन, विद्युत, जल–मार्ग, सड़क परिवहन, दूरसंचार, खद्यान्न और खेती, इंजीनियरिंग उद्योग, स्वास्थ्य–सेवा, जीव विज्ञान और जैव–प्रौद्योगिकी से संबधित दृष्टिकोण शामिल थे।

बहरहाल, टीआईएफएसी द्वारा तैयार की गई इस बहुउद्देशीय परियोजना का जिक्र करते हुए अब मैं आपको बताता हूं कि साल 2020 का भारत आपको कैसा दिखना चाहिए? igyk] यह एक ऐसा देश हो, जहां शहरों और देहातों का अंतर नाममात्र का रह जाए। nljk, जहां बिजली और स्वच्छ पेयजल सबकी पहुंच में हो और सबको ये दोनों समान रूप से मिले। rhljk] जहां देश के विकास में कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र समान रूप से सहायक हो। pkFkk] जहां सामाजिक व आर्थिक भेदभाव के कारण कोई मेधावी छात्र स्तरीय शिक्षा से वचिंत न रहने पाए। ikpok] भारत दुनिया भर के बड़े विद्वानों, वैज्ञानिकों व अविष्कारों के लिए उपयुक्त मंजिल हो। NBk] जहां सबको बेहतरीन स्वास्थ–सेवाएं उपलब्ध हो। lkrok] जहां शासन संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त रहे। vkBok] जहां गरीबी का पूर्ण उन्मूलन हो चुका हो, निरक्षरता मिट चुकी हो, बच्चों व औरतों के खिलाफ अपराध थम चुके हो और समाज में कोई खुद को उपेक्षित न पाए। ukok] भारत एक समृद्ध, स्वास्थ, सुरक्षित, आंतकवाद मुक्त, शांत और खुशहाल राष्ट्र बने और वह वहनीय विकास के मार्ग पर सतत बढ़ता रहे और nlok] भारत बसने के लिहाज से दुनिया के बेहतरीन जगहों में एक हो और उसे अपने नेतृत्व पर गर्व हो। इन सबके लिए हमें उन पांच क्षेत्रों में बदलाव करना होगा, जिनमें यह देश सामार्थ्य रखता है। और ये क्षेत्र हैः कृषि एवं खाद्य–प्रसंस्करण, शिक्षा व सेहत, सूचना एवं संचार–प्रौद्योगिकी, ढ़ांचागत विकास और अहम प्रौद्योगिकियों में आत्म–निर्भरता।

bfM;k fotu&2020 दस्तावेज पीवी नरसिंह राव के शासनकाल में तैयार हुई। इसे बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया, जिन्होंनें संसद में इसको रखा और स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया कि साल 2020 से पहले भारत आर्थिक तौर पर विकसित राष्ट्र बन जाएगा। मेरे राष्ट्रपतिकाल के दौरान राज्यपालों के एक सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी यह घोषणा की थी कि उनकी सरकार देश को आर्थिक समद्धि के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ाने का काम करती रहेगी।

^fdlh Hkh jk"Vªh; fotu* को साकार करने में कम से कम पंद्रह साल लग ही जाते हैं। लोकतात्रिंक तरीके से निर्वाचित कम से कम तीन सरकारों को ऐसे राष्ट्रीय मिशन पर काम करना होता है। jk"Vªh; nf"V&i= को किसी एक पार्टी का एजेंडा नही माना जा सकता, हालांकि ये पार्टियों के चुनावी घोषणा–पत्रों का हिस्सा हो सकता है। सत्ता में मौजूद एक पार्टी के कामकाज का तरीका पिछली पार्टी से अलग हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय विजन सबसे ऊपर है। fotu&2020 का किसी एक पार्टी या सराकर से ताल्लुक नहीं है। यह देश का सपना है। हमारे पास इस विजन को हासिल करने के लिए अब छह साल से भी कम समय बचे हैं। इसलिए देश को प्रथमिकता के साथ इसे लेना चाहिए और इस लक्ष्य को पाने के लिए इससे सभी हितधारकों का मनोबल बढ़ाना चाहिए।

देश ने कृषि उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में काफी प्रगति की है। भारत दुनिया का दुसरा सबसे बड़ा मोबाईल फोन उपभोक्ता देश बन चुका है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के क्षेत्र में हम दुनिया में तीसरा स्थान रखते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण व शहरी विकास योजनाओं ने आधारभूत ढांचों को विस्तार दिया है, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क–मार्ग, मेट्रो शहरों में विश्वस्तरीय हवाई अड्डे वगैरह। साल 2012 में भारत की साक्षरता दर 74.04 फीसदी हो गई थी। मगर इन तमाम कामयाबियों के बीच हमें यह भी देखना है कि 1990 के दशक में हमने क्या सोचा था और उसे पाने में अभी अंतर क्यों हैं ?

यह हमारी राजनीतिक व्यवस्था ही है, जो किसानों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डाक्टरों, शिक्षकों, वकीलों और अन्य पेशेवर लोगों को हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्पेस मिशन, रक्षा मिशन, साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी मिशन और इंफ्रांस्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिशन में देश को कामयाबी दिलाने के लिए जरूरी मदद मुहैया कराती है। आज हम जो कुछ भी हैं, अपनी राजनीतिक व्यवस्था की वजह से हैं। इसलिये देश के नौजवानों को राजनीति, राजनीतिक व्यवस्था से दूरी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि देश को सभी क्षेत्रों में महान बनाने के लिए इसके नेतृत्व, मार्ग–दर्शन व प्रेरणा के वास्ते उन्हें आगे आना चाहिए। युवाओं का मन ऐसी भावना से ओत–प्रोत होता है कि ^eSa ;g dj ldrk gwa* और उन्हें यकीन है कि ^Hkkjr ,d fodflr jk"Vª cuxkA* अगर आप यह महसूस करते हैं कि आप यह कर सकते हैं, तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से भारत पंचायत से लेकर संसद तक रचनात्मक नेतृत्व को पा जाएगा।



आपको सफलता चाहिये तो बस जो आपको अच्छा लगता है, वही करते चले जाइए, सफलता सहज आपको मिल जाएगी। – डेविड फ्रॉस्ट

# आत्मविश्वास

ujUn vkgtk food

आत्मविश्वास मनुष्य जीवन में सफलता का प्रथम सोपान है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें आत्मविश्वास होना चाहिये कि हम इस कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम है। इसलिए अपने स्वयं पर विश्वास जागृत करने के लिए हमें अपनी शक्तियों को भली भांति जान जायेंगे तो निश्चत रूप से हमारे अंदर आत्मबल और विश्वास का संचार होगा जो हमारे जीवन में सफलता का आधार बनेगा। अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए हमें अपनी आत्मा को जानना होगा। हमारी आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, सदा रहने वाली है इस शरीर के जन्म से पूर्व और मृत्यु के उपरांत भी मेरी इस आत्मा का अस्तित्व रहेगा। यह आत्मबोध निश्चित रूप से हमारे अंदर अतुल्य आत्मबल का संचार कर देता है। वैसे भी ऋग्वेद में द्युमां असि क्रवुमा इन्द्र धीरः ।16/2/12 कहकर वेद ने अपनी शक्तियों को पहचानने का आदेश दिया है। ऐश्वर्यशाली आत्मा, प्रकाशमान, क्रियावान और धीर है। जीवात्मा अपनी शक्तियों को पहचान मन, बुद्धि और इन्द्रियों की शक्ति से परिपूर्ण आत्मज्योति से चमकने वाला कर्मशील और धैर्यवान है। यदि हम अपनी इन शक्तियों को पहचान ले तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जायेगा।

वैसे भी ऋग्वेद में ही ßvgfeUnk u ifjkftX;Þ 10 |48 |5 कहकर वेद भगवान ने आत्मविश्वास जागृत करने का आदेश देते हुये कहा मनुष्य इन्द्र है, तू कभी हार नहीं सकता।" आत्मविश्वास जागृत होने पर कोई भी कार्य असम्भव नहीं रहता। जब मनुष्य के हृदय में विश्वास हो जाता है कि "मैं इस कार्य को पूर्ण कर लूंगा" तब वह कभी परास्त नहीं हो सकता। आत्मविश्वासी कठिनाई से भागता नहीं अपितु धीरता पूर्वक उनका सामना करता है। पाश्चात्य विद्वान जार्ज बनौड शा ने तो यह कहा कि कठिनाई और विरोध वह मिट्टी है जिसमें शौर्य और आत्मविश्वास का विकास होता है। इसे यदि दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें तो आसानी से कह सकते हैं कि अपने काम में अटूट श्रद्धा से आत्मविश्वास का विकास होता है। हम जीवन में चाहे किसी पर कितना भी शक करें लेकिन कभी स्वयं अपने या अपनी शक्तियों पर शक ना करें। यदि हम गहराई से चितंन करें तो पायेंगे कि आत्मविश्वास का अभाव ही अंधविश्वासों को जन्म देता है जो हमारे पतन का कारण बनता है। इसलिये वेद भगवान के आदेश अपश्यं गोपाम्। ऋग्वेद 21/77/32 का पालन करते हुए अपनी आत्मा का दर्शन करें अर्थात अपनी आत्मविश्वास को पहचान कर आत्मबल जागृत करके आत्मविश्वासी बनें।

हम कभी भी यह न सोचें कि मैं दीनहीन बेकार कमजोर हूं। हमें तो यह अनमोल तन परमपिता परमेश्वर ने अपनी न्याय व्यवस्था के अनर्तगत हमारे पूर्व जन्मों के सद्कर्मों के फलस्वरूप प्रदान किया है। अपने शरीर के एक–एक अंग की अतुलनीय संरचना को पहचानें। ईश्वर प्रदत्त अनमोल तन को अपने आधीन रखकर अपने आत्मबल से एश्वर्य को प्राप्त करें। वेद भगवान ने भी कहा ßvnhuk% L;ke 'kjn% 'kreAÞ यजुर्वेद 36/24 हम सौ बरस तक दीनता रहित होकर जीवन व्यतीत करें। इसके लिए हमें अपने मन से दीन भावनाओं को छोड़कर अपने जीवन में आत्मविश्वास की दिव्य और उच्च भावना को जागृत करना होगा। इससे हम जीवन के अनेक कार्य में सफल हो कसते हैं। दरअसल आज हमारी स्थिति उस सिंह शासक सरीखी है जो भेड़ों के झुंड में रहकर अपनी पहचान शक्तियों को भूल चुका है। आवश्यकता है खुद को पहचान का आत्मदर्शन द्वारा आत्मबल जागृत करते हुए आत्मविश्वासी होकर धैर्य एवं शौर्य से कर्म करके ऐश्वर्य पाने की।

---

# वैवाहिक विज्ञापन

- SM4 Jat Girl 26/5'3" MCA, MBA Employed as supervisor in Central Govt. on contract basis. Avoid Gotras: Bagri, Nehra, Nain, Cont.: 09417415367
- SM4 Jat Girl 23/5'2" B.Tech (CSE), Avoid Gotra: Malik, Hooda, Joon, Cont.: 09780336094
- SM4 Jat Girl (21.09.1992) 22/5'6", Per suing M.Sc. (Physics) final, Avoid Gotras: Lather, Kharb, Dahiya, Cont.: 09416013723
- SM4 Jat Boy 28/5'10" MBA from Punjab University. Working as Manager in Steel Industry SAIL in Jharkhand. Avoid Gotras: Nashier, Gehlayan, Deswal, Cont.: 09813143850
- SM4 Jat Boy 34/5'11" M.A, M. Sc., H.D.S.E., Employed as Software Manager in ICICI LOMBARD General Insurance Company Ltd. Delhi With 7 Lac Annual & Bonus, Health Insurance benefits. Avoid Gotras: Tomar, Khewal, Cont.: 09729440347

# Sad Demise of the Planning Comission

Ram Niwas Malik

Three months incumbency of ShriNarendraModi indicates that he takes major decisions in a huff which speaks of his political immaturity as a Prime Minister. This is because he comes straight from the state politics and ruling India (A country known for its big size and all forms of diversities) is a different ball game all together than ruling a state of peace loving people. Himachal Pradesh is another state where people do not quarrel with each other with sole exception of politicians. Recently, the Prime Minister took four controversial decisions .i.e. scrapping the Planning Commission, Jan DhanYojana , sacking of Governors and running of bullet train. Scrapping the Planning Commission is the worst ofall. These projects are not bad as such but they have been declared without doing necessary homework in respect of their financial viability and road map for implementation.For example, the Jan-DhanYojana does not eradicate poverty to the extent it is made out to be. It will simply overburden the banks with unnecessary work.Similar is the case of futility of bullet train project if its cost comes to Rs. 100 crore per kmlength. Obviously a mature politician will never make a decision (that too without the cabinet approval) till all the nitty – gritty of the project have been worked out or a pre-feasibility report has been prepared and accepted. Finally such projects generate more heat than light.

Now let us talk about the existence of the Planning Commission. When India became free, the economic scenario in the country was like a devastated and deserted park. The total power generation was only 1350MW.Our freedom fighters were in jail continuously for 34 months before their release in June1945. They had not seen much of the outside world. Their mind set was under the spell of Mahatma Gandhi who in those days rightly believed that Swaraj could come in one year if the people fully utilised their local resources and maintained a sanitary environment. Only Jawaharlal Nehru had an international mind-set and thought differently. When India got Independence on 15th August 1947, the country was trapped under an avalanche of communal violence. To make matters worse,Sardar Patel died in December 1950. Gandhi Ji had remarked that two bullocks (Nehru and Patel) under the same yoke would pull the cart out. They did.

Nehru was rightly impressed with the tremendous progress made by Russia through the mechanism of FIVE-YEAR-PLANS (FYP).A plan with a span of five years is neither short term nor long term perspective. It is the right size for preparing a sound plan document. Accordingly Nehru adopted that model for India.

Now the question was who should prepare the plan document. Science and technology had not developed much in those sterile days of India. So he set up the Planning Commission to perform this job through an executive order. He requested President D.Eisenhour to spareProfessor Johan Gailbraith to assist the Commission in formulating the draft of the firstFYP. Nehru appointed Ashok Mehta as Deputy Chairman of the Planning Commission. He was a brilliant politician but suffered from ideological dogmas. A renowned scientist or a technocrat like Shridharan of DMRC fame would have been the right choice. But still the Planning Commission did a wonderful job in drafting the document of the first FYP in time and India started moving along a trajectory of planned growth. The Prime Minister gave lot of publicity about the preparation and implementation of the first two plans not because of vote bank politics but for spreading awareness amongst the people of India. I remember that SardarPratap Singh Kairon used to speak exhaustively on the success of second FYP in every public meeting.

But the role of Planning Commission gradually became stereo-typed over the years. The draft of the 12thFYP could be looked as the third edition of the 9th FYP.In fact the Commission over-simplified its work. It asked the states and the central ministries to prepare their own planned document (both annual and five year) and the Commission simply fine - tuned these drafts and compiled them to make it Five Year Plan document. The Commission never made serious efforts to gauge the real problems in the country and address them accordingly in the Plandocument. Nor it could prepare a long term economic model for India.

The mandatory functions of the Commission are to prepare a sound FYP document(a road map for economic development), suggest reforms, advise on policy framework and tell the (even warn) the government where the things were going wrong for not meeting the Plan targets. Lately, the Commission performed the first three functions in a lethargic way and abandoned the fourth function completely. The role of the Commission was something like that of RBI in the banking sector where RaghuramRajan is doing a very fine job. He had the guts to tell the Modi government, "RBI should not see things the same way as the government." Montek Singh Ahluwalia miserably failed to mesuareupto the stand of RaghuramRajan.

During the 11thFYP period, Dr Montek Singh Ahluwalia circulated the Concept Paper for the 12FYP and this document was worth dumping into the dustbin. Similarly the report on "Energy" by Kirit Parekh Committee was as insipid as the Concept Paper. The members of the Commission were never appointed on the solecriteria of merit.Most of them have been pseudo-academicians/economists who had little knowledge of ground realities. As the time went on the core competence of the members of the Planning Commission also continued to deteriorate. When Rajeev Gandhi had a look at the 7th FYP document,he called the Commission a bunch of jokers. The right term would have been a bunch ofclass room/armchair specialists. Now the situation has come to suchan impass that approval of the Plan document has become an once-in- five-year ritual. Non fulfilment of targets of the FYP is nobody's concern these days. Nobody in whole of the country knows the contents of the draft document. The document is approved by the National Development Council in half a day deliberations. It is never discussed in the

Parliament. The result is that very few people know that 12th FYP will end on 31 /3/2017.This crass ignorance of the most important document is because the Planning Commission never circulates the summary of the Plan to the educational institutions and government departments.

Recently there have been serious allegation of bias against the Commission. It is said that the Commission has become His Master's Voice. That is why the Commission did not oppose MNEREGA on rational grounds. The other allegation is that the Commission allocates funds according to the wishes of the Central Government.( The Commission distributes funds for centrally sponsored schemes ).Ithas never warned the government for not framing and following a pragmatic policy to control population growth which is responsible for most of the social and economic problems being faced by the country. Similarly the Commission never asked the Ministry of Water Resources Development to put up proposals for water resources and hydropower development. The Commission took no interest in the execution of A.B. Vajpayee's pet project of developing 50,000 MW of hydropower by 2017. Fortunately 95% water storage dams were built during the period of Nehru as the Prime Minister. The Commission never brings out any magazine of international standard. There is not a single book in its library which deals with the causes and remedies to solve the problem of poverty in India. The Commission has also become notorious for spending huge amounts on its toilets and other upholstery.

The state Chief Ministers were always critical of the Commission (Particularly Mr NarendraModi) because the size of the Annual Plan is never fixed according to their wishes. Their common refrain is that the states are not given a free hand in preparing their own model of economic development in the spirit of the concept of "Federal Structure" of the country though the real concept of the term '' Federal Structure "is in the reverse order. On the other hand, states maintain a poorly staffed planning board. In Haryana, the deputy chairman of the planning board is a person who could not be adjusted anywhere in the ministry. At one time, he was a politician who was originally a clerk in the Forest department. The fact of the matter is that Chief Ministers want to rule/treat the states as their personal fiefs to pursue their vote bank politics agenda and populist schemes like free electricity to the farmers or increasing old age pension every year. Look at the money being spent by state governments for the publicity of their achievements through full page advertisements in all the leading newspapers and magazines. Haryana Government has spent money on publicity like water. A PIL has been admitted in the Punjab and Haryana High Court against the state government in this regard. The monthly bill of one of the Hindi newspapers was Rs 1.5 crore per month. The proprietor has now formed a new political outfit. The Finance Ministry is also jealous of the Commission for cross checking itswork. The Finance Ministry never presents the annual budget in line with the plan provisions. That is why Planning Commission, RBI and CAG are always frowned upon by the politicians on flimsy grounds.

As a matter of fact even Dr Manmohan Singh wanted to restructure the Commission and deputed Mr Chibber, an Independent Evaluation Officer (IEO) to prepare a report in this regard. MrChibber , in turn advocated for scrapping the Commission. This report came very handy to the new Prime Minister to take this decision. It was in this background that the Prime Minister overacted and made the declaration during his speech at the Red Fort on 15/8/2014.Normally such decisions are never announced during the Independence Day speeches of the Prime Minister.

The Prime Minister declared that the Commission would be substituted by a new institution(a new body with new soul) and perform the job of a think tank. Thereports in the media suggest that the new body will have only an advisory role and a perfunctory existence. In other words the job of the Planning Commission will be subdued and India will be deviating from the trajectory of planned growth and entering the stage of planning chaos. Just as the country needs a strong centre, likewise it also needs robust centralised planning. As in Japan, sound planning is more important than the quick implementation of projects. But the working style of the Prime Minister so far suggests that he wants to centralize all powers in the PMO. A recent press report states that "The new think-tank will act as a multi-sector advisory body to the PM and will have statutory powers to enable it to implement policies on behalf of the PMO." How can an advisory body will have statutory powers is not known to anybody.

Whatever maybe the flaws in the working of the Planning Commission it does not deserve to be scrapped.All the members of the Planning Commission including the Deputy Chairman gracefully resigned on the very day the new government took the charge. Now the Planning Commission has been placed in animated suspension and there is hardly any work in its Secretariat.12th FYP was to be appraised for applying mid-course corrections. Now it will not be done till a new institution of Mr Modi's dreams is established. The composition of the new institution has not even been conceptualised and it may take at least two years for its establishment. Till then the work of the Commission will remain in limbo and the operation of the 12th FYP will suffer the most.

The causes of all economic ills faced by the country is not so much due to deficient planning as due to the poor implementation of the projects envisaged in the Plan document. Everybody knows about the visionary level of our leaders.They are worse than the men of straw as predicted by Winston Churchill in 1946.It is agreed that Planning Commission is also responsible for the economic ills to some extent (35%) but poor governance is more(65%). Now the politicians want to lay the entire blame at the door of the YojanaBhavan.Therefore it was expected of Shri NarendraModi as a mature politician to weigh all pros and cons of this step before deciding to scrap this old institution in a huff and that too without obtaining the concurrence of the cabinet. The right approach would have been to install a new team consisting of highly competent technocrats, scientists, doctors and economists in the Planning Commission and redefine its role. There is nothing wrong in the existence of the Planning Commission as an institution. It only needs to be recast in its composition. If scrapping the Commission had become indispensable, then it should have been done after the alternate institution was established.

# श्री नयनादेवी जहां सती के नयन गिरे

fgekpy çns'k ds fcykliqj ftys esa xksfcan lkxj >hy ds fdukjs f=dks.k ioZr ij fLFkr Jh u;ukanoh dk efUnj fgUnq&fl[kksa dk lka>k rhFkZLFky gSA ;gka o"kZ Hkj esa rhu cM+s esys yxrs gSA ,d esyk pS= uojk=s esa] nwljk Jko.k 'kqDy v"Vceh vkSj rhljk vkf'ou uojk=ksa esa yxrk gSA blesa Jko.k 'kqDy v"Veh ;kuh lkou&v"Veh esys esa yk[kksa J)kyq ekrk ds efUnj esa ekFkk Vsdus igqaprs gSA

Jh u;ukanoh efUnj rd igqapus ds fy, rhu&lkS lkB ikSfM+;ka p<uh iM+rh gSA bu ikSfM+;ksa }kjk efUnj rd igqapus ds fy, lkr M;ksf<+;ka gSa ftu ij ekW Hkxorh ds pj.kfpUg vafdr gSA ykd ekU;rk gS fd xYr :i ls eka ds x.ks bu M;ksf<+;ksa ij igjk nsrs gSA efUnj ds ços'k }kj ij nk;h vkSj Jh x.ks'k th o lkFk esa gh gueku th dk efUnj gSA cka;h vksj Hkjoh {ks=iky dk LFkku gSA ihiy dh tM+ksa esa cgefiMh fojktekku gSA ;gh Jh y{ehukjk;.k o 'ksr oV+d ftUgs ykcdfM+;k ohj dgk tkrk gS] ds efUnj gSA fLo }kjk ij flag okgu fojktekku gS\

Jh u;ukanoh dh 'kfDr ihB ds :i esa iwtk dh tkrh gSA 'kfDr ihB dh ikSjkf.kd dFkk ds vuqlkj ,d ckj 'kadj Hkxoku th ds llqj n{k çtkifr us cgqr cM+k ;K jpk;kA ogka mUgksaus lHkh nsork vkefU=r fd;s ysfdu viuh nkekn 'kadj th dks ugha cqyk;kA blij Hkxoku 'kadj th dh iRuh ekrk lrh dks cgqr Øks/k vk;kA viuh ifr dk vieku n[kdj rFkk Hkxoku 'kadj ds euk djus ij Hkh og viuh firk nokjk jpk, egk;K esa pyh xbZA 'kadj th us ohjHknz dh v/;{krk esa viuh dN x.k ekrk lrh ds lkFk Hkt fn;sA

viuh firk n{k çtkifr ds ;K esa viuh ifr ds fy, dkbZ vklu fcNk u n[kdj lrh us cgqr çkFkuk dh fd bl rjg ml s o 'kadj th dk viekfur ugha fd;k tk,A ysfdu mlds firk ugha ekusA xLlkbZ ekrk lrh us ;kxkfXu esa viuk 'kjhj dk tyk MkykA ;g vuFkZ n[kdj Hkxoku f'ko ds x.k Øksf/kr gks mBsA ohjHknz dh v/;{krk esa mUgksaus ogka ;K) djds n{k ds ;K dk fo/oal dj fn;kA

lrh ds ;kxkfXu esa ty tkus dk lekpkj feyrs gh Hkkys 'kadj ogha igqap vkSj viuh iRuh dk v/ktyk 'ko dU/ks ij mBkdj ekgo'k rkaMo uR; djrs gq,] Hkkx [kM+s gq,A blds cjs çHkko dks /;ku esa j[krs gq, fo".kq Hkxoku th us viuk lqn'kZu pØ NksM+ fn;k ftlls ekrk lrh ds vax dV&dVdj i`Foh ij fxjus yxsA tgka&tgka tks vax fxjs ogka mlh uke ls ekrk dk efUnj cu x;k vkSj og dgyk;kA tgka lrh ds u;u fxjs ogka Jh u;ukanoh th dk efUnj cukA blfy, ;g 'kfDr ihB dgykus yxkA blh f=dks.k ioZr ij ekrk Jh u;ukanoh us efg"kklqj jk{kl dk Hkh o/k fd;k FkkA

dqynhi pansy

dgk tkrk gS fd ejrs&ejrs efg"kklqj us ekrk ls çkFkuk dh fd ;fn og mlls dksbZ ojnku nsuk pkgrh gS rks ;K dk ,d Hkkx mls feyk djsA blij Hkxorh th us dgk fd ;K Hkkx rks igys gh nsorkvksa ds fy, fuf'pr gSA ysfdu rqe ejs gkFkksa ls ejs gks] blfy, ejs lkFk rqe Hkh iwts tk;ksxsA ekWa Hkxorh rHkh ls f=dks.k ioZr ij fojktekku gSA bls fl) ihB Hkh dgk tkrk gSA ftl ioZr ij ekrk dk efUnj gS mls Jh u;ukanoh /kke Hkh dgk tkrk gSA

Jh u;ukanoh efUnj dh fl)ihB o 'kfDrihB ds vfrfjDr ,frgkfld ekU;rk Hkh gSA uoeh 'krkCnh esa dgyqj fj;klr ¼fcykliqj½ ds lLFkkid jktk ohjpan us ,d Loiu ns[kk Fkk fd ;fn og bl LFkku dk m)kj djs vkSj ;fn vkdj iwtk&ikB djs rks og ,d cgqr cM+s jkT; dk 'kkld cu ldrk gSA ,frgkfld ekU;rk ds vuqlkj jktk ohjpan us bl ioZr ij ekrk Jh u;ukanoh ds efUnj dk fuekZ.k djok dj efUnj LFkkfir dh FkhA efUnj ds uhps fdyk dkV dgyqj cuok;k x;k FkkA vkt mlh fdys esa iqfyl dk Fkkuk dkV gSA

fl[kksa ds nlosa xq: xksfcan flag th us 'kL=vksa dk lgkjk djus ds fy, ekrk Jh u;uk th ds efUnj esa riL;k dh FkhA 'kfDr çkIr djus ds fy, ,d lky rd o yxkrkj ;gka gou djrs jgsA ;gh mUgksaus pMh pfj= uked xzFk dh jpuk dhA ^Jh nsoh lDr* dk Nanc) vuqokn dj JhpMh Hkxoku dh Lrqfr dh gSA blesa efg"kklqj jk{kl dh vgadkjiw.kZ mfDr dk o.kZu xq: th us ;w fd;k gS&

*^bUnz tksgk tks/kk eS;Åa HkfT t;kA*
*dk.kfopkjh nqxkZ ftu j.k lfT t;kA*

,d lky rd J)kiwoZd gou djus ds i'pkr eka nqxkZ çdV gksbZ vkSj xq: th dks ,d ryokj HksaV djrs gq, ojnku fn;k fd rqEgkjh fot; gksxhA ;g ogh ryokj Fkh ftlls ekrk us 'kkg&fu'kkg vkfn jk{klksa dk i/k fd;k FkkA Jh u;uk nsoh fgUnq&fl[kksa dk lka>k rhFkZ LFky gSA ;gka efUnj esa çfrfnu ikp vkjfr;ka gksrh gSA igyh vkjrh lqcg rM+ds pkj cts gksrh gS] iqtkjh jkr dh fcNh 'k;k mBkdj ekgu Hkksx eokfeJh vkfn dk Hkksx yxkdj exy vkjrh mrkjrs gSA mlds i'pkr ekrk th dk Luku djokdj gyok&yMMqvksa dk Hkksx yxk;k tkrk gSA fnu esa 12 cts e/;kà vkjrh gksrh gS ftlesa ikp 0;tuksa lfgr pkoy dk Hkksx yxrk gSA 'kke dks Luku vkfn djok dj pus dk Hkksx yxkdj lè;k vkjrh dh tkrh gSA jkf= dks n/k iMk rFkk ekleh Qyksa ls 'k;u vkjrh gksrh gSA

Jh u;uk nsoh efUnj rd igqapus ds fy, lcls fudV dk jsyos LVs'ku fdjriqj lkfgc gSA ogka ls lM+d ekxZ }kjk ekrk ds efUnj rd igqapk tk ldrk gSA



सफलता आवश्यक नहीं है, किन्तु प्रकाश का अनुकरण करना मेरे लिए आवश्यक है। — अब्राहम लिंकन

# हार्ट सर्जरी में जैड एंजियोप्लास्टी रामबाण

***दैनिक भास्कर से साभार***

हार्ट सर्जरी में अब जैड एंजियोप्लास्टी रामबाण साबित होगी। इंटरवैंशनल कार्डियोलॉजिस्ट व फोर्टिस के डायरैक्टरकार्डियालॉजी डॉ. एच.के.बाली ने दो बायपास सर्जरी और एक बैलुनिंग करवा चुके मरीज के दिल की पेचीदा ब्लॉकेज जैड एंजियोप्लास्टी के दम पर आसानी से ठीक कर दी है। डा. बाली का दावा है कि यह पहली बार है कि जब किसी पेशैंट के दिल को चौथी बार हुई तकलीफ आसानी से दूर हो सकी है। जैड एंजियोप्लास्टी के पहली दफा किए गए इस प्रयोग ने इतिहास रचा दिया है । डॉ. बाल का कहना है कि बायपास सर्जरी करवाने वाले 10 से 20 प्रतिशत पेशैंट्स में आने वाले 10 सालों में फिर बायपास सर्जरी करवाने का रिस्क रहता है। यही नहीं महिलाओं की तुलना में पुरूषों में यह खतरा 90 प्रतिशत होता है। डॉ. बाली ने बताया कि 69 वर्षीय मरीज दलजीत सिंह के दिल पर किया गया यह चौथा प्रोसीजर था। उन्हें 1988 में ट्रिपल वैसल्स कोरोनरी आर्टरी की बिमारी के चलते चैन्नई के एक अस्पताल में बायपास सर्जरी करवा चुके हैं। डॉ. बाली ने बताया कि 1999 में भी इस मरीज की दिल्ली में बायपास सर्जरी हुई थी क्योंकि वह उन्हीं लक्षणों से दोबारा गुजरे थे और उनकी बायपास ग्राफ्ट ब्लॉक हुई थीं। 2014 तक फिर उनमें वैसे कोई लक्षण पैदा नहीं हुए पर हाल ही में वह दिल के दौरे की शिकायत के साथ अस्पताल लाग गए थे। इनकी एंजियोग्राफी में पाया कि एक कोरोनरी आर्टरी में ब्लड वैसल्स सिकुड़ चुके थे। मरीीज पहले भी दो बायपास सर्जरी करवा चुका है। ऐसे में इस ब्लॉकेज का इलाज बेहद मुश्किल था। डॉ. बाली ने बताया कि कई अड़चन ारे मोड़ बन चुके थे जिनके जरिए कोरोनरी बैलून और स्टंट से छेड़छाड़ करना नामुमकिन था। यही नहीं पिछली दो बायपास सर्जरी से और कोई इलाज करना भी मुमकिन नहीं था। डॉ. बाली और उसकी टीम ने इस पेचीदा ब्लॉकेज की एंजियोप्लास्टी की और सफलतापूर्वक स्टेनॉसिस को निकाला और वैस्सल की तरफ के रक्तचाप को वापस दुरूस्त किया। बायपास के बाद वाले मरीज में खुद में यह दुनिया का पहला केस है। डॉ. बाली ने कहा कि इस पेचीदा ब्लॉकेज के इलाज के लिए दो मैडिकेटिड स्टंट प्रयोग किए। लोकल एनैस्थीसिया के प्रभाव में 30 मिनट में इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। मरीज बिल्कुल ठीक है और आम रूटीन जी रहा है।

### ikLV&ck;ikl ejht vkj gkVZ vVSd dk nkckjk gkuk

डॉ. बाली ने कहा कि दिल की बीमारी वक्त के साथ बढ़ती रहती है। इसमें शरीर के वैसल और वैन ग्राफ्ट भी हिस्सा बनते हैं। इन मरीजों में फिर सर्जरी बड़ा खतरा है और शरीर में नाड़ियों की लोकेशन और जटिलता के मनेजर तकनीकी तौर पर एंजियोप्लास्टी की जा सकती है क्योंकि इनमें खतरा कम है। ऐसे में आजतक इन मरीजों में फिर अटैक होने पर सादी मैडिकल थैरपी दी जाती है। जो उनकी जीने की क्वालिटी कम कर देती है। जैड–एंजियोप्लास्टी ऐसे मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। डा. बाली और उनकी टीम ने मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में ऐसे 100 मरीजों में एंजियोप्लास्टी की है।

### vlijf{kr vkj detkj fny

डॉ. बाली ने कहा कि भारतीयों में छोटी उम्र में ही दिल की बिमारी का खतरा रहता है। बाकियों के मुकाबले भारतीय 10 साल पहले ही हार्ट अटैक 45 से कम उम्र, कम स्मोकिंग और कम टैंशन के बावजूद भी भारतीयों की दिल की बिमारी पाश्चत्य जगत के लोगों की तुलना में ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। इन तथ्यों के मध्यनजर डॉ. बाली ने परिणाम निकाला कि बचाव इलाज से बेहतर है। लाइफ स्टाइल में बदलाव करा कोई भी इस बीमारी के फिर होने के खतरे को टाल सकता है।

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

# सत्य बोलकर जीता डाकुओं का दिल

***दैनिक भास्कर से साभार***

अपने माता–पिता को खो चुका एक आठ वर्षीय बालक निखिल दादी के साथ तीर्थयात्रा पर निकला। गांव के कई लोग उनके साथ थे। यात्रा कभी पैदल तो कभी बैलगाड़ी पर होती थी। दादी उसे सदाचार की शिक्षा देती और निखिल उन्हीं के अनुरूप आचरण करता था। एक दिन यात्रा के दौरान निखिल दादी से विछड़ गया और रोने लगा। अचानक वह व्यक्ति मशाल लेकर उसके पास आए। उनमें से एक ने कड़ककर पूछा, तुम कौन हो ? यहां कैसे आए ? निखिल समझ गया कि ये डाकू है। वह भीतर से डर तो गया था पर हिम्मत जुटाकर अपना परिचय दिया। दादी से बिछड़ने की कथा भी सुना दी। डाकू सरदार ने अपने साथियों से उसकी तलाशी लेने को कहा किन्तु तलाशी में कुछ नहीं मिला। डाकू सरदार ने उसे

जाने को कहा पर लिखिल बोला, 'मेरे पास पचास रुपये हैं जो दादी को चप्पल दिलाने के लिए मैंने बचाए थे। उनकी चप्पल टूट गई है और नई खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। पिछले दो साल से बिना चप्पल पहने चल–चलकर उनके पैर सूज गए हैं और छाले पड़ गए हैं। मैं इतने समय से एक–एक पैसा इसी कारण जोड़ रहा था, किन्तु दादी ने सिखाया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए ये रहे पैसे।' यह कहते हुए निखिल ने अपनी टोपी में बनी जेब से पैसे निकालकर डाकू सरदार को दे दिये। बच्चे की ईमानदारी देख सभी डाकूओं का मन भर आया और अपने कृत्य पर पछतावा हुआ। उन्होंने निखिल को पैसे वापस कर उसकी दादी के पास पहुंचाया और स्वयं भी बुरा कार्य छोड़ने का संकल्प लिया। सत्य और ईमानदारी नैतिकता के ऐसे दो प्रकाश स्तम्भ हैं, जो कई बार कुमार्गियों को सही राह पर ला देते हैं।

---

## शाकाहार स्वस्थ जीवन आधार

**jkd!'k lJkgk**

दिनरात कार्य करते रहने से मानव शरीर की शक्ति खर्च होती रहती है। इस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए मानव शरीर को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन को शक्ति वर्धक बनाने के लिए भोजन में प्रोटीन, शर्करा, चिकनाई, खनिज लवण, विटामिन तथा जल जैसे प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है। ये सभी तत्व सब प्रकार की सब्जियों, फलों, अनाज, दालों तथा दुध ा में प्रमुखता से पाये जाते हैं। इन सब का सेवन करना ही शाकाहार कहलाता है। मानव शरीर की संरचना शाकाहार के लिए है। मानव की स्वाभिक प्रवृति एवं आवश्यकता देखते हुए शाकाहार एक पूर्ण आहार है तथा मानव शरीर के लिए सर्वोत्तम भोजन है ताजा फल और शाकाहार व्यक्ति को लम्बी तथा स्वस्थ आयु प्रदान करते है फल और सब्जियों में पाये जाने वालें कई पदार्थ हमारे शरीर से हानिकारक तत्वों को नष्ट करके पेशाव द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते है। इस प्रकार शाकहार स्वास्थ जीवन का प्रमुख आध ार है। आज समस्त विश्व में शाकाहार के प्रति रूझान बढ़ रहा है। शाकाहार के कुछ प्रमुख लाभ निम्न प्रकार से है।

1. शाकाहार जीवन को दीर्घायु, शुद्ध, अलवान एवं स्वस्थ बनाता है। 2. शाकाहारी व्यक्ति मासाहारी की तुलना में अधिक मात्रा में केलोरिज विटामिन एवं प्रोटीन प्राप्त करते है। 3. सरसों का तेल, दालें, हरी सब्जियां एवं चना का उपयोग शरीर में केलोस्ट्रोल की कमी करता है। 4. शाकाहारी भोजन मन में दया, समानता, स्नेह और सहनशीलता बढ़ाता है। 5. नैतिक और अध्यात्मिक दोनों दृष्टि से शाकाहारी भोजन मानव के लिए सर्वोत्तम है। 6. शाकाहारी अधिक उत्पादक है और कम खर्चीला है शाकाहारी कम खर्च से जीवन निर्वाह कर सकता है। 7. अधिकतर शहरी नागरिक कब्ज व सिरदर्द से पीड़ित है। इनसे बचने के लिए फलों व सब्जियों का रस बहुत लाभदायक है। 8. फलहार विटामिन की कमी से होने वाले रोगों से बचाव करता है। कमजोर रोगीं फलों तथा सब्जियों के रसों का उपयोग करके स्वस्थ लाभ प्राप्त कर सकते है। 9. मानव के दातों और आतों की रचना शाकाहारी भोजन के लिए है मासाहार तो हिंसक जानवरों का आहार है। 10. शाकाहारी भोजन मधुमेह रोगी के गुर्दे और तत्रिंका तन्त्र को स्वस्थ रखता है। यह वजन कम करने में सहायक है फल और सब्जियां खानें से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढती है। 11. शाकाहारी भोजन मासांहारी भोजन की तुलना में पौष्टिक एवं स्वास्थ्य के लिए अधिक उपयुक्त है। 12. शाकाहारी भोजन पचाने में शरीर को अधिक समय व जोर नहीं लगाना पड़ता यह सुपाचय है। 13. सभी शक्तिशाली जानवर हाथी घोड़ा तथा बैल आदि नितांत शाकाहारी है। इसलिए भोजन से शरीर में आवश्यक शक्ति का संचार होता है। 14. शाकाहारी भोजन क्रोध, तनाव तथा रक्तचाप को नियन्त्रित करने में सहायक है। 15. शाकाहारी भोजन तथा फलों के सेवन से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

---

## रोबोट करेगा दिमाग की सर्जरी

**okf'kxVy½** यहां एक ऐसा रोबोट बनाया गया है, जो दिमाग में जमे खून के थक्के को एक सुई की तरह निकालेगा। इसे वैनडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता रोबर्ट जे वेबस्टर ने बनाया है इसके उपयोग से सर्जरी में कम से कम नुकसान होगा।

## कितने साल जीएंगे, बताएगा टेस्ट

**ynu½** ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने लेजर डेथ टेस्ट विकसित किया है, जो बता सकेगा कि व्यक्ति कितने साल जी सकेगा। लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एनेटा स्टेफनोवस्का और पीटर मैक्किलंटोक ने इस टेस्ट का पेटेंट कराया हैं।

## हमें जिन पर गर्व है।



जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकुला के आजीवन सदस्य श्री राजबीर सिहाग के सुपुत्र श्री सुबोध सिहाग निवासी सी–63, GH 92 हरकोबैंक सोसायटी सैक्टर 20 पंचकुला ने सी बी.एस.ई. नई दिल्ली द्वारा आयोजित मैट्रिक 2014 की परीक्षा भवन विद्यालय सैक्टर 15 पंचकुला से 9 सी.जी. पीए प्राप्त कर उर्तीण की।

जाट सभा के समस्त सदस्यगण श्री सुबोध सिहाग को इस शानदार सफलता पर उनको बार–बार हार्दिक बधाई देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते है।

# दूसरी नहीं, सतत हरित क्रांति की आवश्यकता

lkeiky 'kkL=h

देश की दो–तिहाई आबादी का जीवन यापन खेतीबाड़ी पर निर्भर है, लेकिन किसी भी सरकार ने इसके समग्र विकास के लिए ठोस प्रयास नहीं किए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि इस क्षेत्र से जुड़ी 60 प्रतिशत से अधिक आबादी के लिए देश के कुल बजट में महज करीब दा फिसद का ही आंवटन किया जाता है। यह स्थिति तब है जब कृषि क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और निर्यात जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर ध्यान देना आवश्यक है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किसी दूसरी या तीसरी हरित क्रांति को लाने की जरूरत है, बल्कि खेती के सतत और समग्र विकास की जरूरत है। यदि मोदी सरकार इस दिशा में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ती है तो उसे सुस्ती के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए`ई मोर्चों पर सफलता मिल जाएगी। जाहिर तौर पर आमदनी बढ़ाने पर किसानों की कंगाली दूर होगी और देश में खुशहाली आएगी।

## ubi Økfr dh t:jr

देश में एक तरह की फसलें उगाने कर परम्परा–सी बन गई है। यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो यहां किसान गेंहू, धान और गनना की खेती पर ही जोर देते आ रहें हैं। देश के अन्य भागों में भी फसलें उगाने के बारे में कमोबेश यही स्थिति है। इसी का दुष्परिणाम है कि देश में कृषि उत्पादन का असंतुलन बन गया है। हम गेंहू और चावल का उत्पादन अपनी जरूरत से ज्रादा कर रहें है जबकि दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे है। हमें बड़ी मात्रा में दाल और खाद्य तेलों का आयात करना पड़ रहा है। देश की बड़ी आबादी शाकाहार पर निर्भर है। ऐसे में जनसंख्या के साथ–साथ दाल और खाद्य तेलों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। बाजार में सब्जी और फलों के भाव काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। इन कीमतों को उत्पादन बढ़ाने के बाद ही काबू में लाया जा सकता है। नई सरकार के लिए कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे इस असंतुलन को दूर किया जा सके। यह फसल चक्र में बदलाव और कृषि क्षेत्र के टिकाऊ विकास से ही संभव हो पाएगा।

## fl apkbi dh 0;oLFkk

आजादी क साढ़े छह दशक बाद भी देश की 60 फीसद कृषि भूमि को सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। देश की 82 फीसद ग्रामीण गरीब आबादी इस क्षेत्र में रहती हैं। खेती के लिए यह क्षेत्र अब भी बारिश पर निर्भर है। यदि मानसून अच्छा रहा तो यहां के लोगों को दो जून की रोटी समय से मिल जाती है और बारिश ने बेरूखी दिखाई तो दाने–दाने के लाले पड़ जाते है। इन लोगों की गरीबी दूर करने के लिए सरकार को देश में बारिश पर निर्भर कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई के साधन विकसित करने होगें। फिलहाल बारिश पर निर्भर कृषि क्षेत्र में औसतन 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खाद्याान्न की पैदावार होती है जबकि सिंचित क्षेत्र मं यह पैदावार 40 क्विंटल के स्तर पर है। यदि सरकार असिचिंत क्षेत्रों में सिंचाई के साधन मुहैया कराने में सफल हो गई तो इससे सालाना 20 करोड़ टन तक ज्यादा खद्यान्न का उत्पादन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यदि वर्षा आधारित क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाएं तो उसका सीधा प्रभाव यह होगा कि देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और मंहगाई जैसी कईं समस्यायें दमर हो सकती है। ऐसे में सरकार को अपने एजेंडें में सिंचाई व्यवस्था को सबसे ऊपर रखना चाहिये।

## Qly dk fofo/khdj.k

हमारे यहां फिलहाल सरकार ने हेंहू और धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। यदि किसान ज्वार, बाजरा, चना और ज्वार जैसे मोटे अनाजों की ज्यादा पैदावार करते हैं तो इस उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता। मजबूरी में उन्हें अपनी फसल औने–पौन दामों में ही बेचनी पड़ती है। इसी बजह से किसान गेंहू और धान की फसल उगाने पर ही ज्यादा जोर देते है। इससे कृषि क्षेत्र में भारी अंसतुलन पैदा हो गया है। खरीद और फसल पर जोखिम होने की बजह से किसान दलहन और तिलहन की फसलें उगाने से परहेज करते हैं। इस बजह से हम दाल और खाद्य तेलों की बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ रहा है। सरकार को इस समस्या को दूर करने के लिए किसानों को फसलों के विविधीकरण की ओर प्रेरित करना होगा। यदि सभी फसलों की खरीद सुनिश्चित हो जाए तो किसान अन्य फसलों की ओर भी आकर्षित होंगें।

## igyh gfjr Økfr ls lcd

कृषि क्षेत्र में पहली हरित क्रांति में सारा जोर सिंचाई के साध्सन विकसित करके और बौनी किस्मों के बीजों का आयात करके उत्पादन बढ़ानें पर जोर दिया गया। इस दौरान सब्जी, फल और पशुधन के विकास के बिना हरित क्रांति सफल हो ही नहीं सकती। हालांकि बौनी किस्मों की फसलों से उत्पादन बढ़ाने में काफी हद तक सफलता मिल भी गई लेकिन इसके कई दुष्परिणाम सामने आए हैं। दरअसल बौनी फसलों को उगाने के लिए काफी अधिक मात्रा में पानी और उर्वरकों की जरूरत होती है। ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने के लिए किसान पानी का भारी दोहन कर रहें हैं। इससे देश में भूजल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इससे सिंचाई के मद में ऊर्जा की ख्पत काफी बढ़ गई है। नाईट्रोजन प्रोटोस और फास्फोरस जैसे उर्वरकों का भारी मात्रा में उपयोग करने से खेतों में से जरूरी अवयव नष्ट होते जा रहे हैं। मृदा असंतुलन बढ़ने से फसलों पर कीट, परजीवी और फंगस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इनसे बचाव के लिए किसान बड़े पैमाने पर कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। लागत बढ़ने से किसानों का मुनाफा भी घटता जा रहा है। दूसरी हरित क्रांतिमें सरकार को मृदा का संतुलन बनाने और फसलों की लागत घटाने पर विशेष जोर देना होगा।

# 100 days of Modi Government

R.N Malik

It has become a regular practice in India to prepare a report card of the first 100 days performance of the government both at the Center and the states. Initially President Rooseveltstarted this practice in 1933 after US came out of the great depression. India did not have depression but had recession and policy paralysis both. Though 100 days is a fraction of the total governance period of 5-years, yet it gives a glimpse of the things to come. Media chronicled the events occurring during 26th May and 3rd September, 2014 and presented the report card of Modi Govt. in different colors. However a truly balanced appraisal has not been made so far which I propose to do so in these columns.

NarenderModi had won three State Assembly elections in Gujrat in a row with comfortable majority though the rural constituencies sent more Opposition MLAs. Consecutive election victories and high grade publicity(by engaging international agencies) of the Gujrat Model of economic development impressed, mesmerized and convinced people in the rest of the country to realize that a new rising star has arrived on the political firmament of Indian politics who could lead the country to a happier millennium. Consequently people brought BJP with thumping victories; firstly in the four state Assemblies in October 2013 and then in the general election of India in May 2014. Mr. NarenderModitook the oath of the office of the Prime Minister on 26th May in the company of heads of SAARC nations and completed 100 days in office on 3rd September 2014.

This clear mandate for the Modi government was for five major expectations

1. Wage a war against poverty, improve the human development index (HDI) and remove the tag of India as an under developed country.
2. Fight against corruption
3. Generation of employment opportunities on a massive scale.
4. Control inflation in food items.
5. Firm up a strategy to beat China in the economic race by 2025 and Shri NarenderModi play the role of Deng Xiaoping as a great game changer.

With this background of public opinion, it was incumbent upon the Prime Minister to prepare a draft road map for economical development of India and address the nation accordingly to instill the trust of the people reposed in him and his government. But the Prime Minister did nothing of this kind. His address on the 15th August 2014 did not hint atany such economic model for development both the Railway and Financial budgets were insipid and uninspiring. On 2nd June, he simply directed his Ministries to prepare detailed notes in respect of the 100 days plans and projects pending for want of required clearances. Ministry of Environment and Forest (MOEF), a big thorn in the flesh of infrastructure development, was specifically asked to clear the projects with sweeping urgency. But so far, MOEF has not given details of projects cleared in first 100 days. It now appears that the new government has either forgotten about its mandate or is simply groping in the darkness. The impression given by the body and speaking language of the Prime Minister and subdued silence of his ministers indicate that he is short ofinnovative ideas and the bureaucracy does not show him the way to move ahead.However he has shown some flashes of his brilliance. The most notable is the rhyme spoken during his recent visit to Japan, "Not red tape but a red carpet awaits you." This jingo will prove a master-stroke in bringing foreign investment provided the investors are given plots in well-developedindustrialestates with 24x7 power supply and allowedto do business with ease. His other proactive steps are:-

1. His hard-talk and no nonsense approach towards his ministers and bureaucracy in respect of good governance to build an environment of self-discipline in the central ministries. His claim that "He is a hard task master and not a headmaster" shows that he means business.
2. The decision to allow 100% FDI in Railway Ministry and 49% in Defense and Insurance sectors.
3. Prevention of water pollution in river Ganges and its tributaries.
4. New impetus to foreign policy particularly in respect of Asian countries. Till now India never looked East in the past and credit for this shift goes entirely to the PM.
5. A nationalsanitation campaign to achieve total sanitation in India by 2nd October 2019 (150th birth anniversary of Mahatma Gandhi).

A clearroad map for National Sanitation Campaign has not been delineated so far. This one program, if implemented systematically and thoroughly, can make India truly shining in 2019. The Jan-DhanYojnawill not cut much ice in eradicating poverty and will only increase burden of clerical work in the banks. His 100 daysof sitting on the PM chair shows that he is the unrivalled boss in the party and the government and that he is very combative, hawkish and even ruthless at times. Reports in the media suggest that PMO will be more powerful than it was during P.N.Haksar days and Mr.Modi is inching towards authoritarianism.He has a penchant for taking controversial decisions and does not bother for public opinion once he has made up his mind


## सम्पादक मंडल

**संरक्षक** : डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)
**सम्पादक** : श्री गुरनाम सिंह, आई.एफ.एस. (सेवानिवृत)
**सह–सम्पादक** : डा॰ राजवन्तीमान
**साज सज्जा एवं आमुख** : श्री आर. के. मलिक
**प्रकाशन समिति** : श्री बी.एस. गिल, मो० : 9888004417
श्री जे.एस. ढिल्लो, मो० : 9416282798
**वितरक** : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़



**जाट भवन 2–बी, सैक्टर 27–ए, चण्डीगढ़**
**फोन : 0172–2654932 फैक्स : 0172–2641127**
Email : jat_sabha@yahoo.com



**Postal Registration No. G/CHD/0107/2012-14** **RNI No. CHABIL/2000/3469**

मुद्रक प्रकाशन एवं सम्पादक गुरनाम सिंह ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोशियटिड प्रिन्टर्ज़, चंडीगढ़, फोन : 0172–2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2-बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27-ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया ।